भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1342

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ पेंशन

1342. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ईपीएफ पेंशन की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तीव्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन संबंधी विकल्प के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करने के लिए निदेश जारी किए हो और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं; और
- (च) क्या ईपीएफओ केरल उच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य है और यदि हां, तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति के मामले पर क्रमशः यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा विशिष्ट अवकाश याचिका (एसएलपी) (सिविल) संख्या 16721-16722/2019 और समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1430-1431/2019 प्रस्तुत कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.07.2019 के आदेश के माध्यम से खुले न्यायालय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूची बनाने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, रिट याचिका (के) संख्या 233/2018 (एम. चोकालिंगम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में दिनांक 06.02.2020 के आदेश के तहत माननीय न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकाओं को पूर्वोक्त एसएलपी और समीक्षा याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

(ख) से (च): यह मामला विचाराधीन है। जैसा की, इस मामले में आगे की कार्रवाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है।